खुदरा व्यापार पर कम्पनियों के हमले का विरोध करो

खुदरा लोकतंत्र के लिए राष्ट्रीय आंदोलन

खुदरा व्यापार में बड़े घरानों के प्रवेश के खिलाफ व्यापारिक संगठन लामबंद

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 26 जुलाई। खुदरा व्यापार में बड़े-बड़े व्यापारिक घरानों और विदेशी कंपनियों के प्रवेश के खिलाफ देश भर के व्यापारिक संगठन व सामाजिक संगठन लामबंद हो गए हैं। ये नौ अगस्त को देशभर में आंदोलन करेंगे। उनकी मांग है कि विदेशी कंपनियां खुदरा व्यापार छोड़ें। दिल्ली में उस दिन चांदनी चौक में रैली निकाली जाएगी और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर खुदरा व्यापार पर कंपनियों के कब्जे को रोकने और लाखों-करोड़ों लोगों की आजीविका बचाने के लिए खुदरा व्यापार के संबंध में राष्ट्रीय नीति बनाने को कहा जाएगा। यह जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता व नवधान्य की निदेशिका वंदना शिवा ने बुधवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में दी। इस मौके पर इंडिया एफडीआई वाच के निदेशक धर्मेंद्र कुमार, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद श्याम बिहारी मिश्रा, [illegible] बचाओ आंदोलन के बनवारी लाल शर्मा, राष्ट्रीय हाकर्स संघ के राजेंद्र रवि भी मौजूद थे।

सामाजिक कार्यकर्ता वंदना शिवा ने कहा कि देश के खुदरा व्यापार को आज असंगठित व्यापार कहकर भ्रम फैलाया जा रहा है जबकि यह व्यापार संगठित है। देश में चारों तरफ लोग अपनी [illegible] के मुताबिक हजारों साप्ताहिक हाट और बाजार लगाते हैं। इससे करीब चार करोड़ लोगों को सम्मानजनक आजीविका मिलती है। यह पूरी तरह से आत्मनिर्भर व्यवस्था है। इसमें पूंजी कम से कम लगती है। पर आज तथाकथित एफडीआई का माडल थोपने के लिए उसे भी अल्प विकसित बताया जा रहा है। इसी तरह देशी-प्रबंधकों को 'दलाल' का नाम दिया जा रहा है और इन्हें खत्म करने के नाम पर [illegible] करोड़ लोगों की रोजी-रोटी छीनने की साजिश रची जा रही है। रिलायंस और वालमार्ट जैसी विशाल कंपनियां आज खुदरा अर्थव्यवस्था पर धीरे-धीरे हावी होती जा रही हैं। वे खुदरा व्यापार में तानाशाह बनने की कोशिश में जुटी हुई हैं और उत्पादन से लेकर विक्रय तक सारी व्यवस्था को "हाई जैक" कर रही हैं। ये अपने आपको किसानों के मुक्तिदाता कहते हैं और दिखावा कर रहे हैं कि ये किसानों और उपभोक्ताओं के मित्र हैं, इसलिए उन्हें मुनाफाखोरों से बचाते हैं। जबकि असलियत कुछ और है। ये होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर सबके मुनाफे पर खुद ही कब्जा करके बड़े दलाल बन गए हैं। इस [illegible] को ये खुदरा क्रांति का नाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सस्ती चीजें खरीदकर किसानों का शोषण कर रहे हैं और बाजार पर अपनी पकड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बाजार पर पकड़ मजबूत हो जाने के बाद ये अपना सामान महंगे दामों पर बेचेंगे।

वंदना शिवा ने कहा कि खुदरा व्यापार में इन बड़ी-बड़ी कंपनियों के प्रवेश से बेरोजगारी बढ़ेगी। इसके अलावा इन बड़ी कंपनियों की घुसपैठ से एक और खतरा सामने आएगा वह है चीन, थाईलैंड समेत आसियान के अन्य देशों से सस्ती वस्तुओं की आपूर्ति है। इससे भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार खत्म हो जाएंगे। यह हमारे निर्माण क्षेत्र खासकर लघु उद्योगों के लिए काफी नुकसानदायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि आज वायु प्रदूषण के कारण वातावरण परिवर्तन पहले से ही मानव जीवन के लिए खतरा बना हुआ है। खुदरा व्यापार में इन कंपनियों के आने से ईंधन की ज्यादा खपत होगी। इससे प्रदूषण फैलेगा। सब्जियों और फलों के प्रशीतन के लिए बिजली की खपत ज्यादा होगी।

पूर्व सांसद व भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम बिहारी मिश्रा ने कहा कि व्यापार के नाम पर आज देश में विदेशी कंपनियां आ रही हैं और देश के बड़े-बड़े औद्योगिक घराने आज मूली, गाजर बेचने पर उतारू हैं। अंबानी, टाटा और बिड़ला को देश में उद्योग लगाने चाहिए न कि छोटे-छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी छीननी चाहिए। इन लोगों के पास पैसा और सत्ता [illegible] की ताकत है।

उन्होंने कहा कि हमारा देश किसानों और मजदूरों का देश है। यहां लोग अपना काम कर रोजी-रोटी चला रहे हैं। पर इन बड़े घरानों की नजर अब खुदरा व्यापार पर टिकी हुई है। सरकार इनका पूरा सहयोग दे रही है। उन्होंने बताया कि देश भर के व्यापारी आठ व नौ अगस्त को हर माल पर दो घंटे धरना देंगे और छह से आठ अगस्त तक हर शहर में विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे।

राष्ट्रीय व्यापार मंडल के बनवारी लाल कंछल और धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि इन प्रदर्शनों में रिलायंस, भारती और वालमार्ट के पुतले जलाकर प्रदर्शनकारी अपना विरोध जताएंगे।

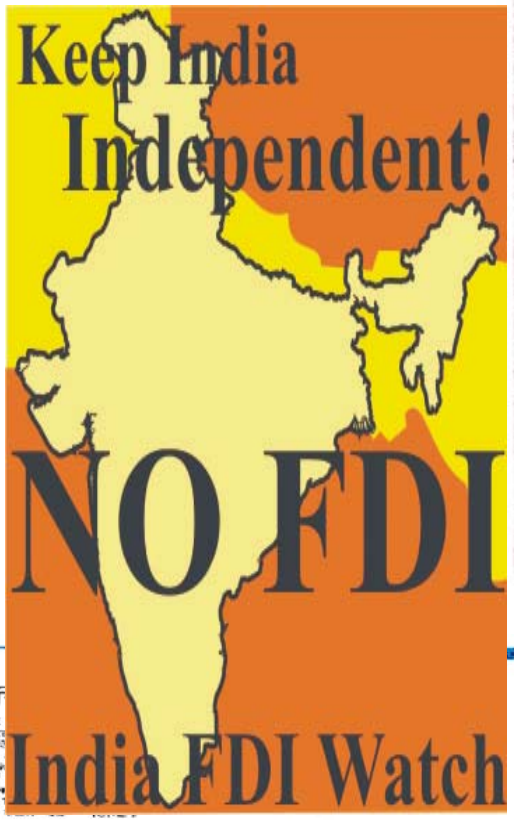

वालमार्ट के सीईओ को दिखाए काले झंडे

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 फरवरी।

विश्व की सबसे बड़ी खुदरा व्यापार कंपनी वालमार्ट के भारतीय खुदरा बाजार में प्रवेश का आज विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर विरोध किया। उद्योग भवन पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। इस बीच वालमार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइकल डिमोक के आज दिल्ली पहुंचने पर व्यापारियों ने उन्हें काले झंडे दिखाए।

खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा वालमार्ट व भारती के बीच हुए करार के विरोध में आज 'इंडिया एफडीआई वाच' के आह्वान पर विभिन्न दलों और संगठनों के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आये। सीपीआईएम, अखिल भारतीय व्यापार महासंघ, सीटू, नेशनल एलायंस आफ पीपुल्स मूवमेंट, हेरिट रिसाइकिल एसो., नेशनल हाकर्स फेडरेशन आदि संगठनों के कार्यकर्ता आज बड़ी संख्या में रफी मार्ग स्थित वीपी हाउस पर एकत्र हुए और वहां से उद्योग भवन तक विरोध मार्च किया। यहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें संसद मार्ग थाने लाया गया। प्रदर्शनकारियों ने थाने पर भी प्रदर्शन जारी रखा।

राज्यसभा सदस्य अबनी राय, सांसद डी. देवराजन, सीपीएम नेता विजयेन्द्र शर्मा, गुरुदास दास गुप्ता, कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स के प्रवीण खंडेलवाल सहित विभिन्न संगठनों के नेताओं ने इसे समर्थन दिया। सांसद अबनी राय ने कहा कि खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश से बेरोजगारी बढ़ेगी व छोटे दुकानदारों का कारोबार चौपट हो जाएगा। इंडिया एफडीआई वाच के संयोजक धर्मेन्द्र कुमार ने कहा कि वालमार्ट को अमानवीय व अनैतिक व्यापार के लिए जाना जाता है, उसे भारत में आने की अनुमति देने से अनियोजित क्षेत्र में न केवल नौकरियां कम होंगी बल्कि मुनाफे का बड़ा हिस्सा भी देश से बाहर चला जाएगा।

व्यापारी बोले, जारी करेंगे श्वेतपत्र

नई दिल्ली, 22 फरवरी (एसएनबी)। विश्व की प्रमुख खुदरा व्यापार कम्पनी वालमार्ट के अधिकारियों के आज भारत आगमन पर कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स ने खुदरा व्यापार पर श्वेतपत्र जारी करने की घोषणा की है।

संगठन के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि वालमार्ट जैसी कंपनियों के आने से देश के करोड़ों छोटे व्यापारी ही बेरोजगार नहीं होंगे बल्कि किसानों, सहकारिता क्षेत्र, कर्मचारियों व लघु व मध्यम उद्योगों पर भी असर पड़ेगा।

इंडिया एफडीआई वॉच

(www.indiafdiwatch.org)

खुदरा-लोकतंत्र पर कारपोरेटी हमला

खुदरा व्यवसाय दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है और इस पर मुट्ठी भर बड़ी कम्पनियों का कब्जा है। ये कम्पनियां मुख्य रूप से अमेरिका और पश्चिमी यूरोप की कम्पनियां हैं। वॉल मार्ट, टेस्को, कार्रेफोर और मैट्रो जैसी विशाल बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने घरेलू बाजारों पर पूरा कब्जा कर चुकी हैं। अब वे भारतीय बाजार पर नजरें गड़ाए हुए हैं। हाल के समय में रिलांयस, टाटा और बिरला जैसे बहुत सारे भारतीय व्यावसायिक घरानों ने भी खुदरा व्यापार में पैर फैलाने का ऐलान किया है।

भारत में लगभग 1.2 करोड़ दुकानें हैं। इस आधार पर भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा दुकानों वाला देश कहा जा सकता है। हमारे देश में होने वाली कुल खुदरा बिक्री में से लगभग 97 प्रतिशत असंगठित खुदरा क्षेत्र के हिस्से में आती है। औद्योगिक खुदरा कम्पनियां संगठित खुदरा व्यापार के हिस्से को अगले चार साल के भीतर 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 15-20 प्रतिशत तक पहुंचा देना चाहती हैं। इसके लिए ये कम्पनियां 25 अरब डॉलर से भी ज्यादा का निवेश करेंगी। इस निवेश में से 60-65 प्रतिशत हिस्सा खुदरा खाद्य एवं किराना क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर निवेश किया जाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि "जो काम दूसरे वैश्विक बाजारों में 25-30 साल में हुआ, भारत उसे 10 साल में करना चाहता है।"

इस बारे में अभी लोगों को बहुत जानकारी नहीं है कि मौजूदा खुदरा और कृषि क्षेत्रों पर औद्योगिक नियंत्रण से क्या असर पड़ेंगे। ये दोनों क्षेत्र फिलहाल रोजगार के सबसे बड़े स्रोत हैं।

भारतीय व्यापार बेहद संगठित है और सदियों से कम लागत और बेहतर कार्यकुशलता के आधार पर चलता रहा है। आज हमें अपने व्यापारियों, दुकानदारों, फेरी वालों और रेहड़ी वालों की काबीलियत की जरूरत है जिससे न केवल करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सके बल्कि समाज की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए समुदायिक सेवाए भी उपलब्ध होती रहें।

हमारे खुदरा लोकतंत्र की कुछ खासियतें

1. *खुदरा क्षेत्र में रोजगारों की भारी संख्या। इस क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है जो कुल रोजगारों का 8 प्रतिशत और हमारी जनसंख्या का 4 प्रतिशत है।*
2. *आत्मसंगठन का उच्च स्तर।*
3. *कम पूंजी लागत।*
4. *भारी विकेन्द्रीकरण।*

दुनिया भर में दुकानों की संख्या और घनत्व के लिहाज से भारत सबसे आगे है। हमारे देश में प्रत्येक हजार लोगों पर 11 दुकानें चलती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय औसत से मिलान किया जाए तो यह संख्या बहुत ऊंची है। लेकिन भारतीय बाजार में मौजूद भारी विकेन्द्रीकरण की वजह से ये सारे व्यवसाय आसानी से चलते रहते हैं और दुनिया के भावी बजारों के लिए एक मॉडल बन सकते हैं।

भारत के खाद्य बाजार में विशाल और औद्योगिक खुदरा कम्पनियों के आने से यहां के 65 करोड़ किसानों और खुदरा व्यापार में लगे 4 करोड़ लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। अगर हम दूसरे देशों का उदाहरण लें तो साफ देख सकते हैं कि कहीं भी इन कम्पनियों ने आम लोगों, समाज और पर्यावरण के बारे में नहीं सोचा। हमारे खाद्य बाजार में इन कम्पनियों की आमद से यहां भी विनाशकारी परिणाम पैदा होंगे। अब समय आ गया है कि हम एकजुट होकर भारतीय खुदरा बाजार पर कब्जे की इन कोशिशों के खिलाफ आंदोलनों का सूत्रपात करें।

खुदरा कम्पनियों की विस्तार योजनाएं

रिलायंस : यह कम्पनी विभिन्न प्रकार की खुदारा दुकानें खोलने के लिए 30,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की तैयारी में है। 2009-10 तक रिलायंस की खुदरा दुकानों से होने वाली बिक्री की कीमत 90,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगी। कम्पनी देश के 784 शहरों और कस्बों में हजारों स्टोर्स खोलने की तैयारी कर रही है।

भारती ग्रुप : यह कम्पनी देश भर में खुदरा नेटवर्क बनाने के लिए 31,500 करोड़ रुपये का निवेश करने वाली है। उसके खुदरा स्टोर्स में से 100 भीमकाय हाइपरमॉल तथा कई सौ छोट स्टोर होंगे।

पेन्टालून : यह कम्पनी तमाम वस्तुओं और उत्पादों के खुदरा व्यापार में पैर जमाना चाहती है। कम्पनी की योजना है कि 2010 तक

खुदरा व्यापार में देशी-विदेशी बड़ी कंपनियों पर पाबंदी का सख्त कानून बनाओ।

तीन करोड़ वर्ग फुट क्षेत्रफल में उसके स्टोर खुल चुके हों। यह कम्पनी बीमा, रीयल एस्टेट और उपभोक्ता फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में काम करेगी और 2010-11 तक उसका सालाना कारोबार 30,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।

आरपीजी : यह कम्पनी आईपीओ जारी करने की तैयारी कर रही है। उसके 450 से ज्यादा म्यूज़िक वर्ल्ड स्टोर, 50 से ज्यादा स्पेन्सर्स हाइपरस्टोर होंगे और 2010 तक उसकी खुदरा ईकाइयों का क्षेत्रफल 40 लाख वर्ग फुट से ज्यादा होगा।

लाइफ स्टाइल : यह कम्पनी अगले 5 साल के भीतर मैक्स हाइपरमार्केट ऐण्ड वैल्यू रिटेल स्टोर्स, होम ऐण्ड लाइफस्टाइल सेंटर्स को विस्तार देने के लिए लगभग 450 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बना चुकी है।

रहेजाज़ : यह कम्पनी शॉपर्स स्टॉप, क्रॉसवर्ड, इनॉर्बिट मॉल, होम स्टॉक और हाल ही में शुरू किए गए हाइपरसिटी नामक हाइपरमार्केट्स की एक विशाल शृंखला तैयार करना चाहती है। कम्पनी की योजना है कि 2015 तक देश भर में उसके 55 हाइपरमार्केट होंगे।

सुभिक्षा : यह कम्पनी मार्च 2007 से पहले 750 स्टोर खोल चुकी थी और उसकी बिक्री 650 करोड़ रुपये से ज्यादा थी।

पिरामिड : यह कम्पनी अगले 5 साल में 150 खुदरा स्टोर खोलना चाहती है जिनका क्षेत्रफल 17.5 लाख वर्ग फुट होगा।

ट्रेन्ट : यह कम्पनी अगले 12 डीएलएफ मॉल्स में 10 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल में 27 नए स्टोर खोलेगी।

त्रिनेत्रा : हाल में इस कम्पनी का एबी बिरला ग्रुप ने अधिग्रहण किया है। त्रिनेत्रा (जिसके फिलहाल दो संस्करण हैं त्रिनेत्रा और फैबमॉल) की योजना है कि 2007-08 के दौरान 300 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार वाले 220 स्टोर खोले जाएं।

विशाल ग्रुप : यह कम्पनी 2010 तक एक आईपीओ जारी करेगी और 1250 करोड़ रुपये का निवश करेगी। यह कम्पनी 220 स्टोर्स खोलना चाहती है जिनका कुल खुदरा क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग फुट और सालाना बिक्री 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा होगी। वित्त वर्ष 2007-2008 के दौरान कम्पनी के 50 से ज्यादा नए स्टोर खुलेंगे जिनमें 300 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और उनकी बिक्री का लक्ष्य 700 करोड़ रुपये से ज्यादा रखा गया है। विशाल रिटेल का मुख्य जोर निम्न-मध्य आय समूह पर रहा है इसलिए यह कम्पनी मुख्य रूप से तीसरी श्रेणी के शहरों में कारोबार फैलाना चाहती है।

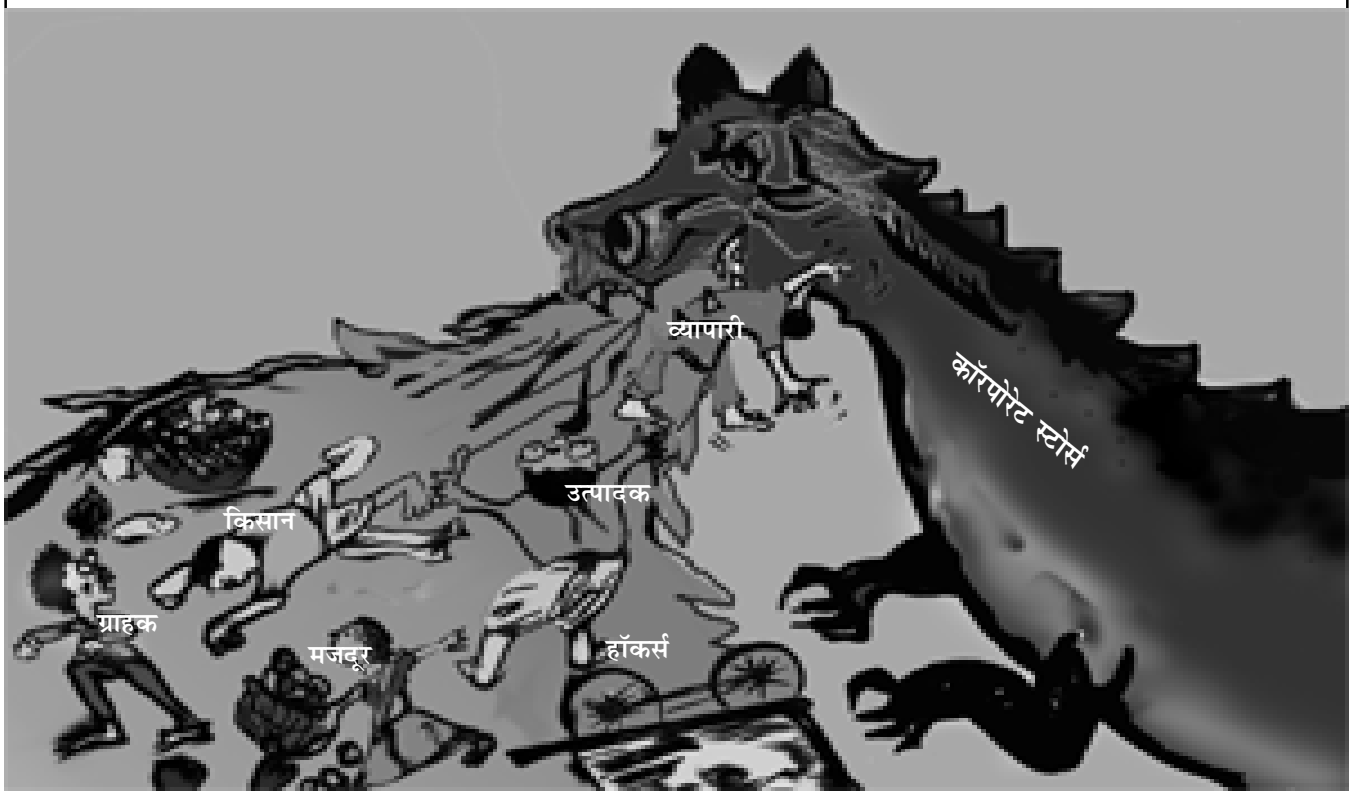

'होलसेल कैश एण्ड कैरी' रद्द करो - वालमार्ट की घुसपैठ पर रोक लगाओ।

मिथक और यथार्थ

मिथक	यथार्थ
उपभोक्ता विशाल औद्योगिक खुदरा कम्पनियां चाहते हैं।	भारतीय उपभोक्ता की सोच "खरीदो और चुकाओ" की पश्चिमी सोच की जगह "बचाओं और खरीदो" वाली रही है। जैसा कि भारतीय उद्योग परिसंघ (कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इण्डस्ट्रीज़) के एक सम्मेलन में पिछले दिनों कहा गया, औद्योगिक खुदरा कम्पनियों को मांग "पैदा करने" और उपभोक्ताओं को खर्च करने के लिए प्रेरित करने पर करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ेंगे।
भारत इतना विशाल देश है कि यहां औद्योगिक खुदरा श्रृंखलाओं और छोटी दुकानों, सबके लिए जगह है।	विकसित देशों में वॉल मार्ट और टेस्को जैसी कम्पनियों का मुकाबला न कर पाने के कारण ऐसी हजारों दुकानें बंद हो चुकी हैं जिन्हें परिवार के लोग ही मिलकर चलाते थे। खुदरा बाजार अब असीमित नहीं है इसलिए औद्योगिक खुदरा क्षेत्र के विकास का नतीजा यह होगा कि स्थानीय दुकानें नष्ट होती जाएंगी। यह बात उन शहरों में देखी जा सकती है जहां रिलायंस फ्रेश ने एक साथ 15-20 स्टोर खोल दिए हैं। इस आक्रामक रणनीति के जरिए कम्पनी पूरे शहर और इलाके में रातोंरात छा जाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर चल रही है।
उपभोक्ताओं को फायदा होगा	रीयल एस्टेट, एयरकंडीशनिंग, पढ़े-लिखे सेल्समैन और सेल्सवूमैन, बिजली की बरबादी और ऐसे ही दूसरे खर्चों का बोझ उपभोक्ताओं को उठाना पड़ेगा। इससे आखिरकार उपभोक्ताओं को ही नुकसान होगा क्योंकि खुदरा कम्पनियां छोटे प्रतिस्पर्धियों को बाजार से खदेड़ देंगी और उनका एकछत्र राज कायम हो जाएगा। ऐसे में उपभोक्ताओं के पास बढ़ी हुई कीमत चुकाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा।
औद्योगिक खुदरा व्यवसाय बिचौलियों को खत्म कर रहा है	औद्योगिक खुदरा व्यवसाय भी उत्पादक, थोक विक्रेता, डिस्ट्रीब्यूटर और खुदरा विक्रेता, सारी भूमिकाओं को निभाते हुए 'खेत से रसोई तक' पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर कब्जा कर लेना चाहता है। इस प्रक्रिया में वह खुद विशाल बिचौलिया बन जाता है और अपने लालच के लिए बाजार को तहस-नहस कर देता है। इस नए व्यवसाय में भंडारण, गोदाम, खरीदारी आदि करने वाली कम्पनियां नए बिचौलियां बन जाएंगी।
औद्योगिक खुदरा व्यवसाय से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी।	कम्पनियों का अनुमान है कि इन बदलावों से लगभग 20 लाख नौकरियां पैदा होंगी। इन आंकड़ों में इस बात पर विचार नहीं किया जा रहा है कि इससे खुदरा क्षेत्र पर आश्रित 20 करोड़ लोग बेरोजगारी या अल्पबेरोजगारी की स्थिति में जा पहुंचेंगे।
किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा	पश्चिम में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला पर औद्योगिक खुदरा कम्पनियों का नियंत्रण हो चुका है। अब किसानों के पास इन्हीं कम्पनियों की शरण में जाने के अलावा और कोई खरीदार नहीं बचा है। इससे इजारेदारी की स्थितियां पैदा हुई हैं जिसमें उनके सामने सिर्फ एक या मुट्ठी भर खरीदार रह गए हैं। किसानों के पास इन कम्पनियों द्वारा तय की गई कीमत पर अपनी उपज बेचने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा है। अपना मुनाफा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए ये कम्पनियां किसानों के साथ अनुबंध करेंगी और उन्हें एक ही फसल पैदा करने पर मजबूर करेंगी। किसानों को इस बात के लिए बाध्य किया जाएगा कि वे आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों का इस्तेमाल करें जिनमें कीटनाशकों और रसायनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिससे जमीन की उपजाऊ क्षमता में कमी आती है। भारत में यह सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका है। कृषि क्षेत्र में खुदरा व्यापारियों के घुसने से ये प्रभाव और स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। हालांकि कृषि क्षेत्र रोजगार और आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत है, फिर भी अभी तक ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है जिससे पता चल सके कि इन बदलावों से हमारी खेती पर लंबे दौर में क्या असर पड़ेंगे।
खुदरा कम्पनियां ताज़ी सब्जियां बेचती हैं	इन सारी दुकानों के मुकाबले फेरी वाले कहीं ताजा सब्जियां लाते हैं। लंबी आपूर्ति श्रृंखला और चीजों को ठंडा रखने की व्यवस्था का मतलब है कि हमारे पास बासी सब्जियां और फल ही पहुंच पाते हैं। इन सब्जियों को ताजा और आकर्षक दिखाने के लिए खुदरा कम्पनियां कीटनाशकों और रसायनों का जम कर इस्तेमाल करती हैं।
औद्योगिक खुदरा व्यवसाय स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करता है	खुदरा कम्पनियां लाखों फेरी वालों, कामगारों और दुकानदारों को बेकार कर देंगी। मैक्सिकों में वॉल मार्ट ने 10 साल के भीतर 20 प्रतिशत खुदरा बाजार पर कब्जा कर लिया था। अब मैक्सिको सरकार स्थानीय व्यवसायों को सुरक्षा प्रदान करने के रास्ते ढूंढ रही है। अमेरिकी बाजार पर वॉल मार्ट के चौतरफा कब्जे के कारण हजारों स्थानीय व्यवसाय बंद हो चुके हैं। थाईलैंड में जब खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को छूट दी गई तो 60,000 छोटी दुकानों पर ताला पड़ गया। खुदरा कम्पनियों ने दुनिया भर में स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का तबाह किया है। भारत में भी उसका यही असर होने वाला है। विदेशी खुदरा कम्पनियां अगर यहां आएंगी तो स्वाभाविक है कि वे यहां से मुनाफा कमा कर अपने देश में ले जाने पर ही जोर देंगी। उन्हें यहां की स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में पैसा लगाने की परवाह नहीं होगी।

खुदरा व्यवसाय में कम्पनियों के प्रवेश का असर : केस स्टडीज़

दुकानदारों, फेरी वालों और व्यापारियों पर पड़ने वाले असर

खेती के बाद खुदरा क्षेत्र हमारे देश में दूसरा सबसे बड़ा व्यवसाय है। 2001 की जनगणना से खुदरा व्यवसाय में लगे लोगों की सही संख्या का पता चलता है। इस जनगणना के अनुसार उस समय थोक और खुदरा व्यापार में लगे 2.69 करोड़ लोग 'मुख्य' और 24 लाख सहायक मजदूर थे। इसका मतलब है कि इस व्यवसाय पर लगभग 3 करोड़ लोग आश्रित हैं। इनमें से 1.1 करोड़ शहरों में और 1.9 करोड़ ग्रामीण इलाकों में सक्रिय हैं। इन 3 करोड़ लोगों में से लगभग 1.7 करोड़ दसवीं पास भी नहीं है। जब 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की आजीविका इस व्यवसाय पर आधारित है तो यदि आश्रितों की संख्या भी जोड़ दी जाए तो संभावित खुदरा क्रांति से प्रभावित होने वालों की संख्या कम से कम 12 करोड़ तक जरूर पहुंच जाएगी। औद्योगिक खुदरा व्यवसाय का विकास भारत में स्वसंगठित छोटे खुदरा व्यवसायों की कीमत पर ही होने वाला है।

अनुसंधानों से पता चलता है कि बेरोजगारी बढ़ने से कई तरह की सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। गरीबी बढ़ती है, शराबखोरी बढ़ जाती है, घरेलू हिंसा, आत्महत्या और अपराधों में इजाफा होता है। राजनीतिक स्थिति भी अस्थिर हो जाती है। यदि हम वॉल मार्ट के अमेरिकी मॉडल को अपनाना चाहते हैं जहां स्टोर्स में काम करने वालों को गरीबी की रेखा से भी नीचे वेतन मिलता है जबकि उंचे ओहदों पर बैठे कर्मचारियों को सालाना लाखों डालर मिलते हैं तो हम एक ऐसे रूझान को अपनाने जा रहे हैं जो अमीर-गरीब के फासले को और बढ़ाता है। इतिहास का सबक है कि इस तरह की खाई से हमेशा सामाजिक अशांति और राजनीतिक अव्यवस्था पैदा हुई है।

मुम्बई में परिवार आधारित खुदरा दुकानों और फेरी वालों पर औद्योगिक खुदरा व्यवसाय का असर

जय हिंद कॉलेज, मुम्बई की प्रोफेसर अनुराधा कल्हन ने तथाकथित असंगतठित खुरदा क्षेत्र पर औद्योगिक खुदरा व्यवसाय के असर का पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया। उन्होंने बिना किसी क्रम के 82 छोटी दुकानों और 29 फेरी वालों को चुना। ये सभी ग्रेटर मुम्बई स्थित एक मॉल के ईर्द-गिर्द एक किलोमीटर की परिधि में स्थित थे। सभी 112 दुकानदारों से बात की गई। पुरानेपन के आधार पर लोअर परेल और बॉम्बे सेंट्रल से एक-एक तथा मुलुंड से दो मॉल्स को भी चुना गया और उनका अध्ययन किया गया। लोअर परेल स्थित छह साल पुराना फीनिक्स मॉल सबसे पुराना मॉल है। मुलुंड के मॉल चार साल पुराने हैं जबकि बॉम्बे सेंट्रल का मॉल अभी कुछ महीने पहले ही चालू हुआ है। मुलुंड के दोनों मॉल्स के असर का पता लगाने के लिए मुलुंड और भांडुप, इन दोनों इलाकों की दुकानों का सर्वेक्षण किया गया।

मुख्य निष्कर्ष

- जिन छोटे कारोबारियों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से 71 प्रतिशत का कहना था कि उनकी बिक्री गिरती जा रही है।
- दुकानों की बिक्री में 25 लाख रुपये तक की गिरावट आई है। सबसे ज्यादा असर 400-500 वर्ग फुट, 300-400 वर्ग फुट और 100 वर्ग फुट से कम क्षेत्रफल वाली दुकानों पर पड़ा है।
- सबसे ज्यादा गिरावट किराने की दुकानों में दिखाई देती है। किराने की 87 प्रतिशत दुकानों की बिक्री में गिरावट आई है।
- 63 प्रतिशत दुकानदारों का कहना था कि उन्हें मॉल्स की वजह से अपना व्यवसाय चौपट होने का खतरा दिखाई दे रहा है। 50 प्रतिशत लोगों को गंभीर खतरा दिखाई देता था। 92 प्रतिशत का कहना था कि उनके बच्चे यह व्यवसाय जारी नहीं रख पाएंगे।
- फेरी वालों को बार-बार उनके ठीयों से हटाया जा रहा है। मॉल्स के ईर्द-गिर्द उनके साथ सबसे ज्यादा जोर-जबर्दस्ती हो रही है। 41 प्रतिशत ने कहा कि अब उन्हें जल्दी-जल्दी हटाया जाने लगा है। 24 प्रतिशत का कहना था कि मॉल के एजेंट उन्हें तंग करते हैं। 17 प्रतिशत ने बताया कि अब उन्हें पहले से ज्यादा घूस और हफ्ता देना पड़ता है।
- 72 प्रतिशत फेरी वालों ने बताया कि उनकी बिक्री में कमी आई है। मुनाफे में कमी की बात तो सभी ने बताई जिसका मतलब है कि उनकी आमदनी गिरती जा रही है।

दिल्ली में रिलायंस फ्रेश स्टोर्स के आसपास की दुकानों और फेरी वालों की स्थिति

- मौजूदा दुकानदारों और फेरी वालों पर औद्योगिक खुदरा स्टोर्स के असर का अध्ययन करने के लिए नवदान्या ने इंडिया एफडीआई वॉच के साथ मिलकर दिल्ली में एक शोध किया। इस शोध में हमने ऐसे 75 दुकानदारों और फेरी वालों से बातचीत की जिनकी दुकानें रिलायंस के खुदरा स्टोर्स के आस-पास एक किलोमीटर के दायरे में हैं।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

- रिलायंस के स्टोर खुलने के बाद 88 प्रतिशत खुदरा कारोबारियों की बिक्री में गिरावट आई है।
- रिलायंस की दुकानें खुलने के बाद 45 प्रतिशत दुकानों की बिक्री में 50 प्रतिशत से ज्यादा कमी आ गई है।

खुदरा व्यापार और लघु उद्योगों पर राष्ट्रीय नीति लाओ।

- 66 प्रतिशत दुकानदार और फेरी वाले 10 साल से ज्यादा समय से यह काम कर रहे थे। उनमें से कुछ तो 30 साल से भी ज्यादा समय से इस व्यवसाय में थे। अब उनके सामने कोई और कारोबार शुरू करने और उसमें सफलता पाने के अवसर बहुत कम हैं।
- 59 प्रतिशत दुकानदारों को लगता है कि उन्हें जल्दी ही अपना काम बंद करना पड़ेगा। 27 प्रतिशत को भविष्य में अपने व्यवसाय में भारी गिरावट की आशंका दिखाई देती है।
- मौजूदा दुकानदारों में से 96 प्रतिशत मंडियों से माल लाते हैं। रिलायंस से माल खरीदने वालों की संख्या केवल 4 प्रतिशत है।
- रिलायंस का असर इतना गहरा है कि इन 75 दुकानदारों में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे रिलायंस की जानकारी न हो।
- 58.6 प्रतिशत दुकानदार 12 घंटे से ज्यादा दुकान खोलते हैं। कुछ दुकानें 14 घंटे से ज्यादा खुलती हैं। यह अवधि औद्योगिक खुदरा स्टोर्स के मुकाबले काफी ज्यादा है।
- लक्ष्मीनगर और पहाड़गंज में सब्जी बेचने वाले बहुत सारे छोटे खुदरा दुकानदारों ने अपना काम बंद कर दिया है। वे महीने भर भी रिलायंस का मुकाबला नहीं कर पाए।

किसानों पर असर

रिलायंस और वॉल मार्ट खुद को किसानों का दोस्त और मुक्तिदाता बताते हैं। वे छोटे व्यापारियों को बिचौलिया कहते हैं जबकि सच यह है कि ये कम्पनियां खुद विशालकाय बिचौलिया बन गई हैं। छोटे व्यापारियों के मामले में किसानों के पास यह चुनने का अधिकार होता है कि वे अपना माल किसको बेचना चाहते हैं। एपीएमसी कानूनों में भी इस बात की व्यवस्था की गई है कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले और उनके सामने केवल एक ही खरीददार नहीं होना चाहिए। परंतु रिलायंस और वॉल मार्ट ने तो ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं जहां बेचने वाले तो बहुत सारे होते हैं लेकिन खरीदार केवल एक होता है। ऐसे में ये कम्पनियां कृषि और विनिर्मित उत्पादों के खरीद मूल्य को जितना चाहे कम कर सकती हैं। उनका दावा है कि वे किसानों को पहले से ज्यादा कीमत चुका रही हैं लेकिन सच यह है कि वे देश भर में केवल मंडियों से सामान खरीदती हैं न कि किसानों से। ऐसे में कि किसानों को कम या ज्यादा कीमत मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता।

देश के विभिन्न भागों में पिछले कुछ सालों के दौरान बहुत सारी मंडियां बंद हो चुकी हैं। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला में बड़ी कम्पनियों के दाखिल होने के बाद मंडियां तेजी से बंद हो रही हैं। इस साल इन कम्पनियों ने किसानों को उससे कहीं बेहतर कीमत दी है जितनी उन्हें मंडियों में मिलती थी लेकिन चिंता की बात यह है कि किसानों के पास अपनी फसल बेचने के विकल्प घटते जा रहे हैं। इसी प्रकार विनिर्मित वस्तुओं के मामले में भी खुदरा कम्पनियों द्वारा अदा की जा रही कीमत अभी ज्यादा हो सकती है लेकिन जब बाकी सारे खरीददार नहीं होंगे तो उत्पादकों के पास अपने उत्पाद बेचने के लिए कितने विकल्प रह जाएंगे। किसान इन कम्पनियों की इच्छा और जरूरत के हिसाब से फसल पैदा करने और उन्हीं की तय की हुई कीमतों पर अपना माल बेचने को मजबूरी होंगे। पश्चिम में किसानों के अनुभव इसी प्रकार के रहे हैं। अगर हम भी इसी दिशा में बढ़ते रहे तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे किसानों को भी ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ेगा।

मजदूरों, सप्लायरों और मौजूदा उद्योगों पर असर

दूसरा खतरा यह है कि औद्योगिक खुदरा कम्पनियों के साथ चीन, थाईलैंड और आसियान देशों में बने सस्ते माल भारत में आने लगेंगे। इससे गैर-बराबरी पर आधारित प्रतिस्पर्धा शुरू होगी और भारत में लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार होते जाएंगे। आज स्थिति यह है कि अगर वॉल मार्ट को एक देश मान लिया जाए तो चीन उसका छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार होगा। जब ये कम्पनियां भारत में दाखिल हो रही हैं तो उन पर इस बात की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है कि वे भारत में बनी चीजें ही बेचेंगी। दूसरी तरफ जैसे-जैसे भारत में औद्योगिक खुदरा व्यापार बढ़ेगा, स्थानीय निर्माताओं पर उनकी ताकत और नियंत्रण भी बढ़ेगा क्योंकि वॉल मार्ट और रिलायंस जैसी विशाल कम्पनियां बहुत बड़े पैमाने पर माल खरीदती हैं इसलिए वे कुछ चुनिंदा निर्माताओं से ही खरीदेंगी और बदले में उन्हें लागत या कीमत कम करने के लिए मजबूर करेंगी। इसका मतलब है कि उन कम्पनियों के मजदूरों को ज्यादा लंबी पारियों में काम करना पड़ेगा, उन्हें कम वेतन मिलेगा और जो कम्पनियां प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाएंगी वे बंद हो जाएंगी।

अध्ययन : सप्लायरों और मजदूरों पर औद्योगिक खुदरा व्यापार का असर

प्रोफेसर अनुराधा कल्हन ने बंगलौर और उसके आसपास सप्लायर फैक्टरियों और उनके मजदूरों का अध्ययन किया है। प्रोफेसर कल्हन ने पाया है कि खुदरा कम्पनियां लचीलेपन, लागत, गुणवत्ता, रफ्तार, सूचना और यातायात प्रौद्योगिकी को आपूर्ति श्रृंखला में सबसे ज्यादा महत्व देती हैं। इसी कारण अब उत्पादन मुख्य आर्थिक गतिविधि नहीं रह गई है। वॉल मार्ट को केन्द्र में रखकर किए गए इस अध्यन के कुछ निष्कर्ष इस प्रकार थे :

- 67 प्रतिशत फैक्टरी मालिकों ने बताया कि वॉल मार्ट के साथ व्यवसाय करने के बाद भी उनका मुनाफा पहले जैसा रहा है। 33 प्रतिशत

‘फेरीवालों पर राष्ट्रीय नीति’ अविलंब लागू करो।

कम्पनियों का कहना था कि उनके मुनाफे में कमी आई है। एक भी कम्पनी का यह कहना नहीं था कि वॉल मार्ट के साथ कारोबार करने से उसका मुनाफा बढ़ गया है।

- भारत में बढ़ती मुद्रास्फीति और उत्पादन लागतों में इजाफे के कारण वॉल मार्ट के साथ कारोबार करते हुए मुनाफे को पहले वाले स्तर पर बनाए रखना लगातार मुश्किल होता जा रहा है।
- हालांकि मुख्य सप्लायर फैक्टरियों को वॉल मार्ट के साथ कारोबार करने में मुनाफा घटने का दबाव दिखाई दे रहा है लेकिन वे इस दबाव को अपनी फैक्टरियों में काम करने वाले असंगठित मजदूरों के सिर पर डाल देते हैं जिन्हें बहुत कम वेतन मिलता है और जिनसे बिना वेतन ओवरटाइम कराया जा सकता है। इसके अलावा वे वैश्विक और भारतीय बाजार में अन्य खरीदार ढूंढने की कोशिश करते हैं।

पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव

बदलती जलवायु

वायु प्रदुषण के कारण मौसम में बदलाव इंसानी जीवन के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। तापमान बढ़ रहा है, समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है और गलेशियर पिघलते जा रहे हैं। इन पर्यावरणीय बदलावों का मतलब है कि हमें जीवाष्म ईंधनों के इस्तेमाल पर ज्यादा से ज्यादा अंकुश लगाना चाहिए। हमारे फेरी वाले, रेहड़ी वाले और किराना स्टोर इस समस्या का बढ़िया समाधान हैं। रिलायंस, भारती-वॉल मार्ट जैसी कम्पनियां और भी ज्यादा मात्रा में जीवाष्म ईंधनों का इस्तेमाल करेंगी और हवा में कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगी। सुपर मार्केट्स के ट्रकों में भी ईंधन का जमकर इस्तेमाल किया जाएगा जिससे और प्रदूषण पैदा होगा। यदि हम सीमित अनुमानों का विश्लेषण करें तो भी पता चलता है कि भारत में सुपर मार्केट्स के ट्रक हर साल कम से कम 70 लाख टन से भी ज्यादा कार्बन डाई ऑक्साइड पैदा करेंगे जिससे देश के नाजुक पर्यावरण पर खतरा और भी बढ़ जाएगा। जब पैट्रोलियम पदार्थ महंगे और दुर्लभ होते जा रहे हैं ऐसे समय इन सुपर मार्केट्स के ट्रक हर साल एक अरब लीटर से भी ज्यादा पैट्रोलियम उत्पादों को हजम कर जाएंगे।

अपनी सब्जियों और फलों को ठंडा रखने और स्टोर्स में एयरकंडीशनिंग के लिए इन कम्पनियों को कम से कम 20,000 मेगावॉट अतिरिक्त बिजली की जरूरत होगी। इतनी उर्जा हासिल करने के लिए हमें करोड़ों टन कोयला जलाना होगा। इतने कोयले के जलने से जो कार्बन डाई ऑक्साइड पैदा होगी उससे देश की जलवायु पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां प्रदूषण और कार्बन डाई ऑक्साइड के मौजूदा उत्सर्जन स्तर से पर्यावरण तबाह हो जाएगा, यहां तक की औद्योगिक खुदरा मॉडल के पैरोकार भी इन खतरों से नहीं बचेंगे।

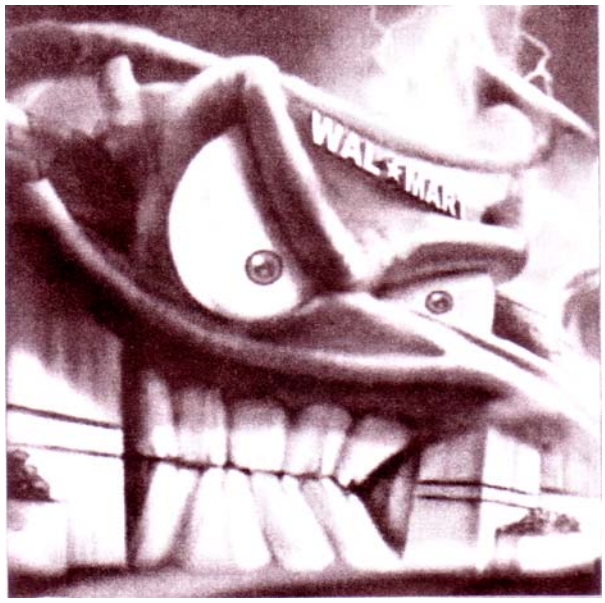

कीटनाशकों के इस्तेमाल में वृद्धि

इन खुदरा कम्पनियों ने गुणवत्ता और खरीदारी के बारे में अपने कुछ नियम तय किए हुए हैं। वे जिस तरह के फल और सब्जियां चाहते हैं उन्हें कीटनाशकों के बेतहाशा इस्तेमाल के बिना पैदा नहीं किया जा सकता। ऐसे में किसानों को कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों का जमकर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये इस तरह के फल और सब्जियां होंगी जो कोल्ड स्टोरेज के जरिए साल भर तक इन खुदरा स्टोर्स में बेची जाएंगी। इस दौरान उनकी 'ताजगी' बनाए रखने के लिए उनमें प्रिजर्वेटिव यानि सरंक्षक रसायनों का भी खूब इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब उपभोक्ता को इन विशाल स्टोरों में रखी सब्जियां मिलेंगी तो वे जहरीले पदार्थों से भर चुकी होंगी।

पैकेजिंग

खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग से शहरों में और ज्यादा समस्या पैदा हो जाएंगी जबकि यहां पहले ही बेहिसाब प्रदूषण जमा हो चुका है। जब देश का हर शहर ठोस कचरे की समस्या से निपटने के रास्ते ढूंढ रहा है, उस समय मॉल संस्कृति के कारण पैकेजिंग से पैदा होने वाला कचरा उनकी मुसीबत और बढ़ा देगा। कचरे को ठिकाने लगाने के लिए बनाए गए मौजूदा लैण्डफिल भरते जा रहे हैं और रिलायंस एवं वॉल मार्ट के पैकेजिंग कचरे से निपटने के लिए गरीब किसानों की और ज्यादा जमीन छीन ली जाएगी।

वॉल मार्ट के बारे में...

यह दुनिया की सबसे बड़ी कम्पनी है। उसकी सालाना आमदनी 350 अरब डालर से ऊपर है। यह आय समूचे भारतीय खुदरा बाजार की आमदनी से भी ज्यादा बैठती है। फिलहाल भारत सरकार ने इस कम्पनी के प्रवेश पर पाबंदी लगी हुई है। अब यह कम्पनी भारती एंटरप्राइज़ेज (एयर टेल)

खुदरा कंपनियों के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक प्रभावों का अध्ययन करने के लिए संबंधित पक्षों को शामिल कर 'स्पेशल टास्क फोर्स' का गठन करो।

के साथ संयुक्त उद्यम की आड़ में पिछले दरवाजे से भारतीय बाजार में घुसने के रास्ते ढूंढ रही है। अभी भारती के साथ करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। इन कम्पनियों को भारत में खुदरा व्यवसाय पर कब्जा करने से रोकना जरूरी है।

- आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले कैनेथ स्टोन द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि अमेरिका के कई ग्रामीण शहरों में वॉल मार्ट के स्टोर खुलने के बाद वहां के खुदरा व्यापार में 47 प्रतिशत की कमी आई है।
- पैन्सिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले स्टीफन जे गोएट्ज़ तथा इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन की हेमा स्वामीनाथन का निष्कर्ष है कि अमेरिका के जिन प्रांतों में वॉल मार्ट के स्टोर खुले हैं वहां के परिवारों में उन प्रातों के मुकाबले ज्यादा गरीबी पाई गई हैं जहां वॉल मार्ट के स्टोर नहीं हैं।
- अमेरिका में सांसद जॉर्ज मिलर के कांग्रेशनल रिसर्च डिपार्टमेंट ने पूरे देश में वॉल मार्ट द्वारा मजदूर अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं का ब्यौरा इकट्ठा किया है।
- डेबिड न्यूमार्क, जूनफू झांग और स्टीफन सिकारेला द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया है कि वॉल मार्ट ने रोजगारों में 2-4 प्रतिशत और वेतन में 5 प्रतिशत की कटौती की है।
- *वर्कफोर्स मैनेजमेंट* में छपे एक लेख में बताया गया है कि वॉल मार्ट के साथ हर साल 6,00,000 नए लोग जुड़ते हैं, यह कम्पनी औरतों के साथ जमकर भेदभाव करती है तथा ओवरटाइम कानूनों का खूब उल्लंघन किया जाता है।
- *मेन स्ट्रीट न्यूज* में छपे एक लेख में बताया गया है कि खुदरा व्यवसाय के क्षेत्रफल में इजाफे से पुलिस की परेशानियां बढ़ जाती हैं, टेलिफोन तथा अन्य संप्रेषण माध्यमों पर लागत बढ़ जाती है तथा उतनी अतिरिक्त आय नहीं होती।

वॉल मार्ट के बारे में कुछ मत्वपूर्ण तथ्य

- हाल ही में वॉल मार्ट को जर्मनी और कोरिया में अपने व्यवसाय बंद करने पड़े क्योंकि वहां कम्पनी लागत से भी कम कीमत पर चीजें बेच रही थी। इन देशों में प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने के लिए ऐसा करने पर पाबंदी है।
- अमेरिका में वॉल मार्ट की 15 लाख महिला कामगारों ने वेतन में भेदभाव के सवाल पर एक बड़ा सामूहिक मुकदमा दायर किया है। इससे पहले एक स्थानीय अदालत कम्पनी के खिलाफ मुकदमा दायर करने की मंजूरी दे चुकी थी। केन्द्रीय न्यायलय ने भी 2004 में स्थानीय न्यायलय द्वारा दिए गए फैसले को सही ठहराया है और उसे वर्तमान तथा भूतपूर्व 15 लाख कर्मचारियों की ओर से सामूहिक रूप से आरोपी ठहराया गया है। यह मुकदमा 2001 में 6 ऐसी महिलाओं ने दायर किया था जो या तो वॉल मार्ट के साथ काम कर रही थीं या कभी उसके लिए काम कर चुकी थीं। सान फ्रान्सिस्को की अदालत ने व्यवस्था दी थी की कम्पनी के खिलाफ मुकदमे को आगे बढ़ाया जा सकता है। यह अब तक किसी निजी कम्पनी के खिलाफ सबसे बड़ा सामूहिक मुकदमा है। न्यायाधीश मार्टिन जेनकिंस का कहना था कि इस मुकदमे में पक्षपातपूर्ण आचरण के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जिनके आधार पर कम्पनी के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। उनका कहना था कि "तथ्यपरक साक्ष्यों, आंकड़ों तथा वादियों के बयानों से इस बात की पर्याप्त पुष्टि हो जाती है कि कम्पनी पक्षपातपूर्ण नीति पर चल रही थी और देश भर में महिला कर्मचारियों को एक जैसे भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था।"

- **वॉल मार्ट को करोड़ों डॉलर का मुआवजा चुकाना पड़ा**

  दुनिया की सबसे बड़ी खुदरा कम्पनी वॉल मार्ट को अपने ऐसे मजदूरों को 7.8 करोड़ डॉलर के बराबर मुआवजा चुकाना पड़ा क्योंकि उन मजदूरों से अवकाश के समय भी काम लिया जा रहा था। पैनीसिल्वेनिया अदालत की ज्यूरी ने फैसला दिया था कि वॉल मार्ट ने मजदूरों को अतिरिक्त श्रम के लिए वेतन न चुका कर कानून का उल्लंघन किया है। यह सामूहिक मुकदमा मार्च 1997 से मई 2006 के बीच वॉल मार्ट के लिए काम करने वाले 1,87,000 कर्मचारियों ने दायर किया था।

- **वॉल मार्ट 'अमेरिका के लिए खतरा' है**

  ज़ोगबी द्वारा हाल ही में कराए गए एक जनमत सर्वेक्षण में वॉल मार्ट को "अमेरिका के लिए खतरा" बताया गया है। इस सर्वेक्षण में ज़ोगबी ने देश भर में 1,012 लोगों से वॉल मार्ट के बारे में उनकी राय पूछी थी। इन लोगों में से 59 प्रतिशत का कहना था कि वे मानते हैं कि "वॉल मार्ट अमेरिका के लिए खतरा है"।

'प्रीडेटरी प्राईसिंग' और कंपनियों की प्रतिस्पर्धा विरोधी रवैये के खिलाफ कानून बनाओ।

- **कार्य स्थितियों की उपेक्षा करने के लिए वॉल मार्ट के खिलाफ मुकदमा**

वॉल मार्ट के खिलाफ दायर किए गए एक मुकदमे में दावा किया गया कि कम्पनी दुनिया भर में अपनी बहुत सारी सप्लायर फैक्टरियों में भयानक कार्य परिस्थितियों को नजरअंदाज कर रही है। यह सामूहिक मुकदमा बंगलादेश, स्वाजीलैंड, इंडोनेशिया, चीन और निकारागुआ के 15 मजदूरों की और से लॉस ऐंजलिस की अदालत में दायर किया गया है। इन सभी मजदूरों का कहना है कि उनको न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन दिया जा रहा था और ओवरटाइम के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता था। कुछ मजदूरों का आरोप था कि उनके साथ मारपीट भी होती थी।

- **मजदूर विरोधी तौर तरीकों के लिए बदनाम**

वॉल मार्ट यूनियन विरोधी तौर तरीकों के लिए दुनिया भर में बदनाम है। कम्पनी मजदूरों को संगठित होने का अधिकार नहीं देती। हाल ही में चीन की सरकार के दबाव में कम्पनी को अपने मजदूरों को यूनियन बनाने का अधिकार देना पड़ा। चीन में भी मजदूर बहुत कम लागत पर दिन रात कम्पनी के लिए माल बनाते हैं। यूनाइटेड फूड ऐण्ड कमर्शियल वर्कर्स के प्रतिनिधि अर्नेस्ट डुरान का कहना है कि सामूहिक सौदेबाजी की तमाम कोशिशों का वॉल मार्ट ने हमेशा विरोध किया है।

- **वॉल मार्ट के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट**

अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 1 मई 2007 को अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में वॉल मार्ट की यूनियन विरोधी गतिविधियों का खुलासा किया गया था। "डिस्काउंटिंग राइट्स : वॉल माट्र्स वायलेशन ऑफ यूएस वर्कर्स राइट टू फ्रीडम आफ एसोसिएशन" शीर्षक इस रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया है कि "अमेरिका में बहुत सारी कम्पनियां कमजोर कानूनों का फायदा उठाकर मजदूरों को संगठित होने से रोकने का प्रयास करती हैं लेकिन वॉल मार्ट की आक्रामकता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता'' क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा ताकत है। ह्यूमन राइट्स वॉच की तफ्तीश से पता चला कि वॉल मार्ट अपने कामगारों और प्रबंधकों को काम पर रखने के दिन से ही उन्हें यूनियनों के खिलाफ तैयार करने लगती है। प्रबंधकों को इस बात की साफ हिदायत दी जाती है कि वे यूनियनों को पैर न जमाने दें। इस तरह की कई शर्तें 'मैनेजर्स टूलबाक्स' में उल्लिखित हैं। उसमें बताया गया है कि किस तरह मैनेजरों को 'अपनी कम्पनी को यूनियनों से आजाद रखना चाहिए क्योंकि यूनियन बनाने वाले कभी भी आपकी ईकाई को निशाना बना सकते हैं।'

- **सप्लायरों पर असर**

मुख्य सप्लायर फैक्टरियों को वॉल मार्ट के साथ कारोबार करने में मुनाफा घटने का दबाव दिखाई दे रहा है लेकिन वे इस दबाव को अपनी फैक्टरियों में काम करने वाले असंगठित मजदूरों के सिर पर डाल देते हैं जिन्हें बहुत कम वेतन मिलता है और जिनसे बिना वेतन ओवरटाइम कराया जा सकता है। बंगलौर की सप्लायर फैक्टरियों में मजदूरों का औसत वेतन उन फैक्टरियों के मजदूरों के औसत वेतन से कम है जो वॉल मार्ट को माल सप्लाई नहीं करतीं (प्रोफेसर अनुराधा कल्हन द्वारा किए गए अनुसंधान पर आधारित)।

कम्पनियों को खुदरा व्यवसाय से खदेडने की मुहिम

अब वक्त आ चुका है कि समाज का हर तबका खुदरा व्यवसाय में औद्योगिक कम्पनियों की घुसपैठ के नतीजों को समझे और इस शैतान को मार भगाने के लिए कमर कसे। यह फेरी वालों, व्यापारियों, किसानों, उपभोक्ताओं, परिवहन कर्मियों, समाज के सभी तबकों के लिए खतरनाक है इसलिए इन कम्पनियों के झांसे में आने से बचना जरूरी है। ये ऐसी कम्पनियां हैं जिन्होंने कभी किसी समाज की फिक्र नहीं की है। वे किसी भी कीमत पर अपने मुनाफे की फिक्र करती हैं। आइए संकल्प लें कि इन कम्पनियों ने पश्चिम में जो तबाही मचाई है, उसे हम भारत में नहीं होने देंगे।

वॉल मार्ट, रिलायंस और टेस्को जैसी विशाल खुदरा कम्पनियां रोजगारों, समुदायों और पर्यावरण की तबाही का परवाना बन गई हैं। दुनिया भर में स्थानीय किसानों और सड़क बाजारों को संगठित करने के लिए आंदोलन चल रहे हैं जिससे सुपर मार्केट्स की एकाश्म संस्कृति और इजारेदारी को तोड़ा जा सके। भारत में वह विविधता और विकेन्द्रीकरण मौजूद है जिसकी पश्चिम के लोग चाह रखते हैं। आइए संकल्प लें कि हम अपने समृद्ध और शक्तिशाली लघु खुदरा क्षेत्र को तबाह नहीं होने देंगे। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम इन स्टोर्स से माल नहीं खरीदेंगे। आइए अपने विविधतापूर्ण विकेन्द्रित खुदरा लोकतंत्र की रक्षा करें। आइए अपने परम्परागत खुदरा क्षेत्र पर कब्जे के खिलाफ आंदोलन में शामिल हों और इस क्षेत्र पर निर्भर करोड़ों लोगों की आजीविका बचाने में मदद दें। आजीविका बचाओ, नागरिक बचाओ। भारत की आजादी की रक्षा करो।

केस स्टडीज

थाईलैंड

यहां 1997 से बहुराष्ट्रीय खुदरा कम्पनियां आने लगी थी। महज कुछ सालों के भीतर उन्होंने खुदरा बाजार के 10 प्रतिशत से भी ज्यादा हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था। बहुत सारी छोटी और परम्परागत खुदरा दुकानें बंद हो गई थीं। बहुराष्ट्रीय खुदरा कम्पनियों ने अपने प्रतिस्पर्धियों

को तबाह करने के लिए लागत से भी कम कीमत पर माल बेचना शुरू कर दिया। इस मुहिम से लगभग 60,000 छोटे खुदरा व्यवासायी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। परम्परागत प्रांतीय थोक विक्रेताओं को भी कारोबार बंद करने पर विवश कर दिया क्योंकि बहुराष्ट्रीय खुदरा कम्पनियों ने भंडारण व वितरण की नई व्यवस्था विकसित कर ली थी। बहुत सारे उत्पादकों को अपना काम बंद करना पड़ा क्योंकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की आक्रामक सौदेबाजी के कारण उनका मुनाफा गिरता जा रहा था (मुखर्जी, *एफडीआई रिटेल सेक्टर इन इंडिया*)।

थाइलैंड के प्रधानमंत्री इस बात को मानते हैं कि घरेलू खुदरा व्यवसाय पर विदेशी खुदरा कम्पनियों का असर नकारात्मक रहा है। आखिरकार थाईलैंड सरकार को स्थानीय खुदरा कारोबारियों की मदद के लिए अलग से एक कोष की स्थापना करनी पड़ी और बहुराष्ट्रीय खुदरा दुकानों के लिए कार्यक्षेत्र तय करने पड़े (*फाइनेंशियल टाइम्स*, विकास अध्यन केंद्र)।

इंडोनेशिया

1997-98 में बहुराष्ट्रीय विशाल खुदरा कम्पनियों के खिलाफ कई जगह दंगे हुए। छोटे स्थानीय खुदरा व्यापारियों और सप्लायरों को सरकार ने आश्वासन दिया था कि बड़ी खुदरा कम्पनियों के आने से वे वैश्विक बाजार के सम्पर्क में आ जाएंगे जिससे उन्हें फायदा होगा। परंतु ऐसे व्यापारियों में से केवल उन मुट्ठी भर व्यापारियों को ही थोड़ा बहुत फायदा मिला जिन्हें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने चुना था।

ज्यादातर स्थानीय सप्लायरों को इन कम्पनियों ने अपने साथ काम करने के लायक नहीं माना क्योंकि वे इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा तय मानकों का इतनी जल्दी पालन नहीं कर सकते थे। एफएओ के अध्ययन में दर्शाया गया है कि विदेशी बड़ी खुदरा कम्पनियां उन संक्रमणकालीन समस्याओं पर ध्यान नहीं देतीं जो किसी देश में उनके दाखिल होने के कारण वहां के छोटे खुदरा व्यापारियों और सप्लायरों को झेलनी पड़ती हैं। स्थानीय कारोबारियों का माल वापस आने लगता है, उनको समय पर भुगतान नहीं मिलता और उन्हें कर्जे मिलने बंद हो जाते हैं (शर्मा, *ईपीडब्ल्यू*)।

चीन

चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सकारात्मक प्रभावों के बारे में काफी कुछ कहा जाता रहा है लेकिन इस बात को चिन्हित करना जरूरी है कि वहां भी छोटे खुदरा व्यावसायी कारोबार में टिके रहने की समस्या से जूझ रहे हैं। एशियाई विकास बैंक (जो खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का समर्थक है) के एक दस्तावेज में यह चिंता व्यक्त की गई थी कि खुदरा व्यापार में स्पर्धा से खाद्य एवं व्यापारिक सेवाओं में सक्रिय छोटे निजी उद्यम बंद होने लगेंगे। चीनी मीडिया में ऐसी घटनाएं हर रोज आती रहती हैं जहां विदेशी कम्पनियों के कारण छोटे परम्परागत कारोबारी सड़क पर आ गए हैं।

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 1992 में चीन ने जब अपने खुदरा क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए खोला था तो उस पर कई तरह के नियंत्रण थे। केवल 6 शहरों में अधिकतम 49 प्रतिशत विदेशी स्वामित्व वाले संयुक्त उद्यमों को ही मंजूरी दी गई थी। किसी भी शहर में इन कम्पनियों के स्टोर्स की संख्या भी 2-4 से ज्यादा नहीं हो सकती थी। खुदरा कम्पनियों को चीनी स्वामित्व वाले व्यवसायों और चीनी नियंत्रण वाले संयुक्त उद्यम खुदरा व्यवसाय तक ही सीमित रखा गया था और वे केवल चीन में बनी चीजें ही बेच सकते थे (मुखर्जी, *एफडीआई रिटेल सेक्टर इन इंडिया*)।

अमेरिका

अमेरिका में वॉल मार्ट तथा संगठित खुदरा व्यापार के विकास का जम कर विरोध किया गया है और इससे स्थानीय समुदायों पर बहुत सारे नकारात्मक असर पड़े हैं। 2004 के अध्ययन में पाया गया कि जिन प्रांतों में 1987 में वॉल मार्ट के ज्यादा स्टोर थे और जहां 1997-98 के दौरान अतिरिक्त नए स्टोर खोले गए वहां नब्बे के दशक में आए आर्थिक उछाल के बावजूद गरीबी में या तो औसत से ज्यादा इजाफा हुआ या बहुत मामूली गिरावट आई।

अध्ययन का निष्कर्ष है कि वॉल मार्ट के स्टोर स्थानीय उद्यमियों और समुदायों के नेताओं को बाहर खदेड़ देते हैं (गोएट्ज़, *वॉल मार्ट और ग्रामीण गरीबी*)।

एक और अध्ययन में पाया गया कि वॉल मार्ट के आने से छोटे खुदरा प्रतिष्ठानों की संख्या में गिरावट आई है तथा अमेरिका में थोक व्यवसाय में रोजगारों पर नकारात्मक असर पड़ा है (भास्कर, *वर्किंग पेपर*)। इस दस्तावेज में कहा गया है कि "उपभोक्ता खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए अपने जाने पहचाने किराना स्टोर्स की बजाय सुपर स्टोर्स तथा हाइपर मार्केट्स में जाना ज्यादा पसंद करने लगे हैं" (भास्कर)। 1988 में सामान्य किराना दुकानों से की गई खरीदारी कुल उपभोक्ता खाद्य व्यय का 42.8 प्रतिशत थी। 1998 में यह मात्रा गिरकर केवल 13.4 प्रतिशत रह गई थी। स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और छोटे व्यवसायों पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण अमेरिका के मुख्य शहरों में वॉल मार्ट के घुसने का काफी विरोध किया गया है। शिकागो, फिलाडेल्फिया, लास ऐंजलिस और न्यू यॉर्क आदि शहरों में इस आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है। न्यू यॉर्क में अभी भी वॉल मार्ट को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है।

> *"अन्य देशों की केस स्टेडीज को देखने पर यह आवश्यकता साफ दिखाई देती है कि छोटे किसानों/सप्लायरों को मदद देने के लिए विकास कार्यक्रम और सरकारी सहायता की रूपरेखा तैयार की जाए"* (मुखर्जी, *एफडीआई रिटेल सेक्टर इन इंडिया*)।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर लगी पाबंदियां

- चीन सरकार ने शुरुआत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आधार पर खुदरा क्षेत्र में केवल ऐसे संयुक्त उद्यम खोलने के प्रस्ताव पर ही मंजूरी दी थी जिनमें विदेशी स्वामित्व 49 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा। उनके लिए शहरों की संख्या भी तय कर दी गई थी और एक शहर में स्टोर्स की अधिकतम संख्या भी निर्धारित थी।
- मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और जापान ने विशाल खुदरा कम्पनियों के व्यवसाय पर भौगालिक पाबंदियां लगाई गई।

- श्रीलंका में विदेशी खुदरा कम्पनियों के लिए न्यूनतम पूंजीगत शर्तें लागू हैं।
- फिलीपींस ने विदेशी खुदरा कम्पनियों पर "सोर्सिंग" और पारस्परिकता की शर्त लगाई हुई है।
- जापान में नया स्टोर खोलने से पहले बड़ी खुदरा कम्पनियों को स्थानीय छोटे दुकानदारों की राय और अनुमति लेनी पड़ती है।
- अमेरिका में लॉस ऐंजलिस, कैलिफॉर्निया, शिकागो और न्यू यॉर्क जैसे बड़े शहरों में वॉल मार्ट के स्टोर खोलने पर कई तरह की पाबंदियां लागू हैं।
- फ्रांस सरकार ने 300 वर्ग फुट से ज्यादा बड़े हाइपर मार्केट्स के विकास पर अंकुश लगाने के लिए रफायरिन कानून पारित किया है।
- थाईलैंड सरकार ने स्थानीय खुदरा व्यापारियों को बड़ी बहुराष्ट्रीय खुदरा कम्पनियों के असर से बचाने के लिए एक सहायता कोष स्थापित किया है।

विश्वव्यापी प्रतिरोध

- सितंबर 2005 में रॉटरडेम, हालैंड के लोगों ने अपने शहर में वॉल मार्ट के आने का जमकर विरोध किया।
- चीन में वॉल मार्ट की एक फैक्टरी के बाहर 10,000 से ज्यादा महिला कामगारों ने हड़ताल कर दी। इन मजदूरों की मांग थी कि कम्पनी बेहतर कार्य परिस्थियां उपलब्ध कराए और उन्हें संगठित होने का अधिकार दे।
- कनाडा में वॉल मार्ट के कर्मचारियों ने यूनियन बनाने के प्रस्ताव के समर्थन में मत दिया था। इसके जवाब में वॉल मार्ट ने स्टोर ही बंद कर दिया। इस फैसले के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने आंदोलन चलाया।
- अमेरिका में 300 से ज्यादा समुदायों ने अपने समुदायों के भीतर वॉल मार्ट के प्रवेश का सफलता पूर्वक विरोध किया है। 2005 में वॉल मार्ट के खिलाफ एक राष्ट्रीय अभियान चलाया गया।
- 1997-98 में जब इन बड़ी खुदरा कम्पनियों के कारण स्थानीय सप्लायरों और दुकानदारों के कारोबार चौपट हो गए तो कम्पनी के खिलाफ कई जगह दंगे भड़क उठे।

खुदरा व्यापार से कम्पनियों को बाहर भगाने के लिए लामबन्द हों

अब समय आ गया है, जब समाज के सभी वर्गों को परचूनी कारोबार में कंपनियों के हमले के खतरों को समझना है और इन राक्षसों से लड़ने के लिए एकजुट होना है। यह फेरीवालों, व्यापारियों, किसानों, उपभोक्ताओं, ट्रांसपोर्ट लाइन के लोगों यानी समाज के सभी वर्गों के लिए खतरनाक है। कंपनियों की चालबाजियों से सावधान हो जाएइ। वे कभी किसी समाज का भला नहीं करतीं। उन्हें हर कीमत पर केवल पर केवल अपना मुनाफा चाहिए। पश्चिम की तरह कहीं हमारे देश को भी इनके द्वारा किये गए विनाश की कीमत न चुकानी पड़े।

वालमार्ट, रिलायंस और टेस्को जैसे बड़े खुदरा व्यापारी रोजगार, समाज, पर्यावरण के विनाश के एजेन्ट हैं। किसानों और गलियों के बाजारों को बचाने और सुपर मार्केट की एकाधिकारी प्रवृत्ति का विरोध करने के लिए विश्वव्यापी आंदोलन हो रहे हैं। जिस विविधता और विकेन्द्रीकरण की पश्चिम को तलाश है। वह भारत में पहले से मौजूद है, हमें अपनी ऐसी लघु-खुदरा व्यवस्था को बचाना है। आइए अपने परम्परागत परचूनी कारोबार पर हमले के खिलाफ आंदोलन में जुट जाए और उन करोड़ों लोगों का साथ दें, जो इससे अपनी रोजी चलाते हैं। अपना व्यापार, रोजगार, बचाइए। भारत को आजाद रखिए।

हमारी मांगे : -

- खुदरा व्यापार में देशी-विदेशी बड़ी कंपनियों पर पाबंदी का सख्त कानून बनाओ।
- 'होलसेल कैश एण्ड कैरी' रद्द करो - वालमार्ट की घुसपैठ पर रोक लगाओ।
- खुदरा व्यापार और लघु उद्योगों पर राष्ट्रीय नीति लाओ।
- 'फेरीवालों पर राष्ट्रीय नीति' अविलंब लागू करो।
- खुदरा कंपनियों के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक प्रभावों का अध्ययन करने के लिए संबंधित पक्षों को शामिल कर 'स्पेशल टास्क फोर्स' का गठन करो।
- 'प्रीडेटरी प्राईसिंग' और कंपनियों की प्रतिस्पर्धा विरोधी रवैये के खिलाफ कानून बनाओ।
- APMC कानून में 'मॉडल' बदलावों को समाप्त करो।

इंडिया एफडीआई वॉच

इंडिया एफडीआई वॉच बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारत के खुदरा व्यवसाय पर कब्जे को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करने और जरूरी कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाला संगठन है। हम ऐसे लोगों के नेतृत्व में ज्वांइट एक्शन कमेटियां (जेएसी) बना रहे हैं जो इन बदलावों के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। अब तक हमने व्यापारिक संगठनों, यूनियनों, फेरी वालों के संगठनों, किसान संगठनों और लघु उद्योगों के साथ मिलकर संयुक्त समीतियां बनाई हैं।

दिल्ली में एक नैशनल स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। इंडिया एफडीआई वॉच इस कमेटी का फेसिलिटेटर और घटक है। यह नैशनल स्टीयरिंग कमेटी अब व्यापार रोजगार बचाओ आंदोलन के बैनर तले काम कर रही है। मुम्बई में एफडीआई वॉच व्यापार रोजगार सुरक्षा कृति समीति का अध्यक्ष और घटक संगठन है। बंगलौर में इंडिया एफडीआई वॉच औद्योगिक खुदरा व्यवसाय के खिलाफ बनाई गई कर्नाटक ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एक प्रमुख सदस्य और संयोजक है।

नैशनल स्टीयरिंग कमेटी देश भर में सक्रिय साझीदारों तथा मुम्बई और बंगलौर में स्थित ज्वाइंट एक्शन कमेटियों के साथ मिलकर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक कार्रवाई करने और प्रभावितों की सुरक्षा के लिए नीतिगत बदलाव लाने पर जोर दे रही है। अगले साल भर के दौरान इंडिया एफडीआई वॉच नैशनल स्टीयरिंग कमेटी के साथ मिलकर इस अभियान के जनाधार को फैलाने के लिए प्रयास करेगा। देश भर में सक्रिय जनसंगठनों को भी इस मुहिम में शामिल किया जाएगा।

इंडिया एफडीआई वॉच राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाहियों को समन्वित और संचालित करने में मुख्य शक्ति रहा है। भारती के साथ संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वॉल मार्ट के उपाध्यक्ष की भारत यात्रा के समय 22 फरवरी को एक महत्वपूर्ण विरोध कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अभी इन दोनों कम्पनियों के बीच करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। अब सोनिया गांधी के साथ-साथ प्रधानमंत्री कार्यलय ने भी वाणिज्य मंत्रालय को आगाह किया है कि वह इस बारे में कोई फैसला लेने से पहले मौजूदा खुदरा व्यापारियों, किसानों और निर्माताओं पर खुदरा क्षेत्र में बड़ी कम्पनियों की घुसपैठ से होने वाले असर का अच्छी तरह अध्ययन कर लें। इस संदर्भ में अध्ययन अभी जारी है।

9 अगस्त 2007 को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर इंडिया एफडीआई वॉच एक राष्ट्रीय विरोध दिवस के तौर पर अपने राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सहयोगियों के साथ मिलकर "कम्पनियों खुदरा छोड़ो" आंदोलन छेड़ने जा रहा है। इस दौरान देश भर में आंदोलन चलाया जाएगा और केन्द्र एवं राज्य सरकारों को आंदोलन की मांगों से अवगत कराया जाएगा।

व्यापार रोजगार बचाओ आन्दोलन में सहयोगी संगठन

एर्को-इंडिया एफडीआई वॉच, नवधान्य-रिसर्च फाउन्डेशन फार साइन्स टेक्नोलॉसी एंड इकॉलॉजी, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, राष्ट्रीय व्यापार मंडल, युटीयूसी-एलएस, लोकराज संगठन, एक्शन इंडिया, राष्ट्रीय मजदूर अधिकार, मंच, कन्ज्यूमर वॉइस, आजादी बचाओ आन्दोलन, सॉलिडैश्रिटी यूथ मूवमेंट केरल, भारतीय मजदूर संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उर्जा, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन, स्वराज स्थापना आन्दोलन भोपाल, हिंद मजदूर किसान पंचायत, आल इंडिया किसान सभा, दिल्ली हॉकर्स वेल्फेयर एसोसिएशन, आल इंडिया किसान सभा, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आल इंडिया कॉआर्डिनेशन कमेटी ऑव ट्रेड यूनियन्स, अपना बाजार, असंगठित श्रमिक पंचायत, पवनपुत्र रेहड़ी-पटरी खोमचा संघ, असंगठित मजदूर यूनियन, बैंगलोर फोरम फॉर स्ट्रीट एंड वर्किंग चिल्ड्रेन, भारतीय खादी निगम कर्मचारी संघ, बहुमुक्ति महिला संगठन, ब्रिज नेटवर्क, बाम्बे ट्रेडर्स फेडरेशन, बैंगलोर हौकरर्स एंड वेंडर्स फेडरेशन, सेंटर, फार इंडियन ट्रेड यूनियन, कन्फेडरेशन ऑव आल इंडिया ट्रेडर्स, सेंटर फॉर एडवांसमेंट ऑव विलेज इकॉनॉमी, कारवां कर्नाटक, कासूम, चाईल्ड राइट एक्शन राइट एक्शन फोरम, दिल्ली असंगठित निर्माण मजदूर यूनियन, फेरीवाला विकास महासंघ, गारमेंट वर्कर्स यूनियन, हिन्द मजदूर सभा, हेजार्ड सेंटर, हरित रिसाइकिलर्स एसोसिएशन, हॉकर्स मौलिक अधिकार सुरक्षा मंच, जागोंर, जनपहल, किसान लोक अभियान, कर्नाटक ट्रकड युनियन सेंटर, एनएपीएम, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन, राष्ट्रीय कामगार संगठन, नेशनल सेंटर फॉर एडवोंकेसी स्टडीज, सिक्योरिटी गार्ड यूनियन, स्लम ज्वांइट एक्सन कमेटी, स्लम विमेन्स फेडरेशन, मलेशरन, सॉलिडेरिटी सेंटर, स्टेट एलांइस फॉर एजूकेशन, विकास अध्ययन केन्द्र यूथ इन यूनिटी फार वालन्टिरी एक्शन, अर्बन स्ट्रीट वेंडर रेहड़ी पटरी हॉकर्स फेडरेशन, सौहार्द ओकुता कर्नाटक, परस्पर ट्रस्ट, पौरा कार्मिक संगठन कर्नाटक।

सम्पर्क : दिल्ली – धमेन्द्र कुमार मोबाईल : 0-9871179084
मुम्बई – विनोद सेठी मोबाईल : 0-9820510146
बैंगलोर – बाबू खान मोबाईल : 0-9343859687

धर्मेन्द्र कुमार द्वारा : इण्डिया एफडीआई वाच द्वारा जारी, ईमेल : **dkfordignity@yahoo.co.uk**